



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 6 सितम्बर, 2000/15 भाद्रपद, 1922

हिमाचल प्रदेश सरकार

FOOD AND SUPPLIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 24th August, 2000

No. FDS-A (4) 2/98.—In exercise of powers vested in him under Articles 102 (3), 102 (5), 102 (7) of the Memorandum and Articles of Association of the H. P. State Civil Supplies Corporation Limited, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to appoint Shri Jai Ram Thakur, M. L. A. as non-official Director on the Board of the Directors of the Himachal Pradesh State Civil Supplies Corporation Limited for a period of two years or till the date of holding the present rank whichever is earlier with immediate effect.

2. In exercise of the powers vested in him under Articles 102 (7) of the Articles of Association of the H. P. State Civil Supplies Corporation Limited, the Governor, Himachal

Pradesh is further pleased to appoint Shri Jai Ram Thakur, M. L. A. as Vice Chairman of the said Corporation with immediate effect. The terms and conditions are being issued separately.

By order,
S. S. NEGI,
Financial Commissioner-cum-Secretary.

IRRIGATION & PUBLIC HEALTH DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 7th August, 2000

No. PBW-(PH) (3)-18/86-III.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Himachal Pradesh Water Supply Act, 1968 (Act No. 8 of 1969) the Governor, Himachal Pradesh is pleased to fix/enhance the security, connections charges and application fee for domestic and commercial connections of supply of water through private connections in rural and urban areas of the Pradesh as under :—

	Rural		Urban	
	Domestic	Commercial	Domestic	Commercial
Security	Rs. 100/-	Rs. 200/-	Rs. 150/-	Rs. 300/-
Connection	Rs. 100/-	Rs. 200/-	Rs. 150/-	Rs. 300/-
Application fee	Rs. 50/-	Rs. 100/-	Rs. 50/-	Rs. 100/-

These rates will come into force with effect from 1-8-2000.

By order,
SARITA PRASAD,
F. C.-cum-Secretary.

पंचायती राज विभाग

आदेश

शिमला-9, 25 अगस्त, 2000

संख्या पी0सी0एच0एच0ए0 (5) 63/98—टिक्करी डसाकना-19010-18.—यह कि श्री बलवीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत टिक्करी डसाकना, विकास खण्ड संगड़ाह, जिला सिरमौर को मु0 19520/- रुपये की अग्रिम धनराशि के दुरुपयोग में संलिप्त पाए जाने के कारण दिनांक 1-1-99 को निलम्बित किया गया तथा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अन्तर्गत आरोपों की वास्तविकता जानने हेतु इनके विरुद्ध नियमित जांच के आदेश कर उप-मण्डलाधिकारी (ना0) के नाहन को विभाग समसंख्यक आदेश दिनांक 24-3-99 को जांच सौंपी गई।

यह कि उप-मण्डलाधिकारी (ना०), नाहन (जांच अधिकारी) द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 23-7-99 व उस पर विभाग द्वारा उठाई गई आपत्तियों का समाधान करते हुए दिनांक 22-2-2000 अनुसार सरकार के विचारार्थ प्राप्त हुई।

यह कि जांच के समक्ष आए तथ्यों से यह निष्कर्ष निकला है कि उक्त प्रधान द्वारा पंचायत निधि का दुरुपयोग अल्प अवधि के लिए अनभिज्ञता के कारण किया गया था ज्ञात होने पर उस द्वारा विवादास्पद राशि व उस पर बना ब्याज मु० 3100/- रुपये पंचायत निधि में तुरन्त जमा करवा दिये जिस कारण पंचायत की धनराशि की क्षतिपूर्ति हो गई।

और यह कि पंचायती राज संस्थाओं के न्यून स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायत पदाधिकारियों की भागीदारी में बढ़ोतरी करने के उद्देश्य से सरकार ने नरम रवैया अपनाने हुए प्रधान द्वारा की गई अनियमित-ताओं/अनभिज्ञता स्वरूप अल्प अवधि के लिये दुरुपयोग की गई राशि की अनदेखी करने का निर्णय लिया है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उन शक्तियों का प्रयोग करने हुए जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 148 में प्रदत्त है, उपरोक्त श्री बलवीर सिंह, प्रधान, के विरुद्ध जांच के निष्कर्षों तथा व्याप्ति को ध्यान में रखते हुए उन्हें दोषारोपण में मुक्त कर उन्हें चेतावनी देने हैं कि वे भविष्य में अपने पद के दायित्वों का निर्वाहन मदेव पंचायती राज अधिनियम, व तदधीन बताये गए नियमों के अनुरूप करेंगे।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उक्त श्री बलवीर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत टिकरी उमाकना, विकास खण्ड मंगड़ाह, जिला मिरमौर के उपरोक्त निलम्बन आदेश दिनांक 1-1-99 को सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के फलस्वरूप, इन आदेशों के जारी होने की तिथि से रद्द करने के सहर्ष आदेश प्रदान करने हैं।

शिमला-9, 29 जुलाई, 2000

संख्या पी० सी० एच०-एच०ए (5) मशीनर-15644-56.—यह कि श्री चन्तर सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत मशीनर विकास खण्ड मोलन, जिला मोलन को उपायुक्त सोलन द्वारा कार्यालय आदेश सं० एस०एल० एन०-12-159 (डैव)/73-3001-07, दिनांक 3-7-2000 द्वारा निम्नलिखित आरोपों में संलग्न पाए जाने के कारण प्रधान पद से निलम्बित किया गया :—

1. यह कि श्रीमती विद्या देवी पत्नी श्री रत्न लाल, निवासी लोहासन महारणी को मु०-15,000/- रु० इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत मकान निर्माण हेतु विभाग द्वारा आवंटित किए गए परन्तु जो मकान उक्त राशि से निमित्त बताया गया है वह मकान वास्तव में श्रीमती विद्या देवी के देवर का है तथा उसके देवर का लड़का उसमें निवास कर रहा है। इससे स्पष्ट है कि प्रधान की मिलीभगत से लाभार्थी ने सरकारी धनराशि का दुरुपयोग किया है,
2. यह कि सिंचाई कुहल मनुह टिकरी से भाग-II सहायक अभियन्ता (विकास) मोलन की निरीक्षण रिपोर्ट अनुसार कुहल कुछ ही भाग तक बनी है बाकी अभी तक बस्ती तक नहीं पहुंची है। कुहल की खुदायी का सारा कार्य श्रमदान में स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। इस कुहल का सहायक अभियन्ता (विकास) सोलन द्वारा टैस्ट चंक किया गया जिसमें पाया गया कि कुहल की दीवार कहीं टूटी हुई है तथा कुहल का लेबल ठीक नहीं है जिससे पानी अच्छी तरह बह सके। कुहल का निर्माण कार्य घटिया स्तर का किया गया है। जिससे पानी होता है कि स्कीम के लिए जो मु० 70,000/- रु० की राशि दी गई थी उसका उपयोग पूर्णतया नहीं हुआ है। अतः

उक्त श्री चत्तर सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मशीबर उक्त राशि के दुरुपयोग करने के दोषी पाए गए हैं।

और यह कि निलम्बन के दृष्टिगत अब राज्य सरकार ने उक्त मामले में हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम (संशोधन), 2000 की धारा 145(3) के अन्तर्गत विहित अवधि में नियमित/विभागीय जांच पूर्ण करवाने का जनहित में निर्णय लिया है,

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल उन शक्तियों के अन्तर्गत जो कि उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम (संशोधन), 2000 की धारा 145(3) में प्रदत्त है, का प्रयोग करते हुए उपरोक्त श्री चत्तर सिंह, प्रधान (नि०) ग्राम पंचायत मशीबर, विकास खण्ड सोलन के विरुद्ध कथित आरोपों की जांच हेतु उप-मण्डलाधिकारी (ना०) सोलन को जांच अधिकारी तथा जिला अंकेक्षण अधिकारी कार्यालय जिला पंचायत अधिकारी सोलन को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हुये जांच अधिकारी से अनुरोध किया जाता है कि वे उपरोक्त आरोपों की जांच एक माह के भीतर- भीतर पूर्ण करके राज्य सरकार को प्रस्तुत करें ताकि निर्धारित अवधि के भीतर- भीतर अन्तिम निर्णय लिया जा सके। श्री चत्तर सिंह, प्रधान (नि०), ग्राम पंचायत मशीबर, विकास खण्ड सोलन को भी यह निर्देश दिए जाते हैं कि वे जांच अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-

आयुक्त एवं सचिव (पंचायत)।